Endorsements for "PEOPLES' VACCINE IN INDIA: A collective letter to PM - Oxfam India and Forum for Medical Ethics Society" भारत में सार्वजनिक टीकाकरण के लिए प्रधानमंत्री जी को जनता की चिट्ठी पर हस्ताक्षर के लिए आवेदन –ऑक्सफैम इंडिया और फोरम फॉर मेडिकल एथिक्स सोसाइटी

कोविड -१९ महामारी ने हम सबको भयभीत कर दिया है। अनियंत्रित रहने पर यह महामारी लाखों के लिए जानलेवा है और करोड़ों को गुरबत में डाल सकती हैं। सभी के लिए नैतिक व सुरक्षित रूप से टीकाकरण सुनिश्चित करने पर कई जानें बचेंगी तथा स्वास्थ्य व्यवस्था पर भार कम होगा, जिससे भारत बेहतर तरीके से महामारी से निपट पाएगा, ताकि सामान्य जीवन बहाल हो सके। भारत में जल्द ही टीकाकरण की दर बढाने की सख़्त ज़रूरत है, ख़ास तौर से कमजोर तबकों के लिए।

इस स्थिति में केंद्र सरकार का नेतृत्व करना जरुरी है। यह न केवल सरकार का नैतिक कर्तव्य हैं, बल्कि समय की मांग है , क्योंकि कुछ ही महीनों में यह वायरस रूपांतर (mutate) कर सकता है, तब शायद अधिकतर शुरुआती टीके असरदार न रहे। बहुत सारे भारतीय इस टीके को खरीद नहीं सकते, जिसकी कीमत भारत की जनसंख्या के निचले तबके के २० प्रतिशत नागरिकों की मासिक आय का करीबन ४३ प्रतिशत है। कोविड टीके के उत्पादकों को इस कठिनाई के समय पर मुनाफे के बारे में न सोचकर, जनता के स्वास्थ्य अधिकार पर ध्यान देना चाहिए। खास तौर से, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया बिना निजी लाभ के, टीके को सभी तक सुलभता से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इन्हें ध्यान में रखते हुए, हम सरकार से सार्वजनिक मुफ़्त टीकाकरण की मांग करते हैं। सरकार को कोविड टीकाकरण पर एक विस्तृत, समय–बाध्य व पारदर्शी नीति और कार्ययोजना बनाना चाहिए, जो राज्यों, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, तथा नागरिकों के परामर्श व सुझाव से तैयार हो , साथ ही, सरकार की फार्मा कंपनियों के साथ किये गए अनुबंधों में पारदर्शिता होनी चाहिए।

अतः, हम सरकार से यह सुनिश्चित करने की मांग करते हैं, कि-:

१. टीका की खरीदारी वाजिब मूल्य पर हो व टीका सभी को निःशुल्क उपलब्ध हो।

२. टीका के निर्धारण में हाई–रिस्क जनसंख्या को प्राथमिकता दें, एवं डिजिटल गैरबराबरी को ध्यान रखते हुए समाज के सीमान्त तबकों तक टीकाकरण पहुंचें, चाहे वह जहां भी रहते हो।

३. टीकाकरण नीति केंद्र सरकार द्वारा विशाल–स्तरीय टीका की खरीद पर ध्यान दें , ताकि राज्यों की आर्थिक क्षमता पर असर न हो, व प्रांतों को एक दूसरे से इस जीवनदायी टीके की खरीद में प्रतियोगिता न करना पड़े।

४. सार्वजनिक स्वास्थ को मजबूत करने के लिए वित्तीय ढांचा तत्काल बेहतर करें। इसको मुमकिन करने के लिए सभी विकल्प अपनाएं, जैसे कि टीका का लाइसेंसिंग अनिवार्य करना, सार्वजनिक क्षेत्र में टीका- उत्पादन बढ़ाना, कोरोना की अगली संभावित लहर का सामना करने सार्वजनिक स्वास्थ के ढांचे को बेहतर तरीके से तैयार रखना ।

हम टीकाकरण पर भारत की विश्व–स्तरीय पैरवी को भी समर्थन देते है, खास तौर से:

१. सामायिक तौर पर विश्व व्यापार संगठन (डबलू. टी. ओ.) के ट्रिप्स (टी.आर.आई. पी.एस.) के अंतर्गत

प्रावधान जैसे कि बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट, इत्यादि पर छूट मिले ताकि समूचे विश्व को निशुल्क टीकाकरण उपलब्ध हो सके।

२. विकसित देशों की वैक्सीन राष्ट्रवादी नीतियों का प्रतिरोध करते हुए टीका के उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया जाए।

३. विकसित देशों में जहां अतिरिक्त वैक्सीन स्टॉक्स होने की आशंका है, उन्हें विकासशील व गरीब देशों में बांट दिया जाए।

मांगो के अधिक जानकारी के लिए निम्न लिंक पर ऑक्सफैम इंडिया– एफ.एम. इ. एस. के पॉलिसी ब्रीफ को पढ़ सकते है। Http://bit.ly/VaccineforAll

इस याचिका के समर्थन के लिए, कृपया निम्न फॉर्म को भरे: